



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 90]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 2, 2009/फाल्गुन 11, 1930

No. 90]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 2, 2009/PHALGUNA 11, 1930

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(अनुसूचित जाति विकास प्रभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 2 मार्च, 2009

सं. 17015/17/2008-आर.आई. सैल.—भारत सरकार के दिनांक 9-9-2004 के संकल्प संख्या 17015/18/2003-एस.सी. डी.-VI और दिनांक 28-12-2007 के संकल्प संख्या 17015/8/2007-आर.आई.सैल के अनुसरण में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल को एतद्वारा निम्नलिखित विचारार्थ विषयों के साथ दिनांक 1-4-2009 से 31-3-2010 तक की अवधि के लिए बढ़ाया जाता है :—

- (क) सफाई कर्मचारियों के लिए स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानता समाप्त करने के लिए कार्य योजना के अधीन विनिर्दिष्ट कार्यक्रमों की केन्द्रीय सरकार को सिफारिश करना;
- (ख) सफाई कर्मचारियों और विशेषकर स्केवेंजर्स के सामाजिक व आर्थिक पुनर्वास से संबंधित कार्यक्रमों एवं स्कीमों के क्रियान्वयन का अध्ययन व मूल्यांकन करना;
- (ग) विनिर्दिष्ट शिकायतों की जांच करना और निम्नलिखित को क्रियान्वित न किए जाने से संबंधित विषयों पर अपनी ओर से ध्यान देना :—
 - (i) सफाई कर्मचारियों के किसी समूह की बाबत कार्यक्रम या स्कीमें;

(ii) सफाई कर्मचारियों की कठिनाइयों को कम करने के लिए विनिश्चय, मार्गदर्शन या अनुदेश;

(iii) सफाई कर्मचारियों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए उपाय;

(iv) सफाई कर्मचारियों को लागू किसी विधि के उपबंध; और ऐसे विषयों को संबंधित प्राधिकारियों अथवा केन्द्रीय या राज्य सरकारों के साथ उठाना;

(घ) कार्य की स्थितियों का अध्ययन और मानीटरिंग जो सरकार, नगर निगमों और पंचायतों सहित विभिन्न प्रकार के नियोक्ताओं के अंतर्गत कार्य करने वाले सफाई कर्मचारियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और मजदूरी से संबंधित हैं और इस संबंध में सिफारिशें करना;

(ङ) सफाई कर्मचारियों को जिन कठिनाइयों या नियोग्यताओं का सामना करना पड़ रहा है, उनको ध्यान में रखते हुए सफाई कर्मचारियों से संबंधित किसी विषय पर केन्द्रीय और राज्य सरकारों को रिपोर्ट देना;

(च) कोई अन्य विषय, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा उसे निर्देशित किया जाए।

2. आयोग के गठन, इसकी शक्तियों, कार्यविधि मामलों और इसकी वार्षिक रिपोर्ट को तैयार करने को दिनांक 9-9-2004 के उपर्युक्त संकल्प के पैरा 3 और 5-7 द्वारा शासित किया जाता रहेगा।

पी. पी. मित्रा, संयुक्त सचिव

[PART I SEC. 1]

**MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND
EMPOWERMENT**
(SCHEDULED CASTES DEVELOPMENT DIVISION)

RESOLUTION

New Delhi, the 2nd March, 2009

No. 17015/17/2008-RI Cell.— In continuation of the Government of India Resolutions No. 17015/18/2003-SCD-VI dated 9-9-2004 and No. 17015/8/2007-RI Cell dated 28-12-2007, the term of the National Commission for Safai Karamcharis is hereby extended for a further period from 1-4-2009 to 31-3-2010 with the following terms of reference :

- (a) Recommend to the Central Government specific programmes of action towards elimination of inequalities in status, facilities and opportunities for Safai Karamcharis;
- (b) Study and evaluate the implementation of the programmes and schemes relating to the social and economic rehabilitation of Safai Karamcharis and scavengers in particular;
- (c) Investigate specific grievances and to take *suo motu* notice of matters relating to non-implementation of:
 - (i) programmes or schemes in respect of any group of Safai Karamcharis;

- (ii) decisions, guidelines or instructions aimed at mitigating the hardship of Safai Karamcharis;
- (iii) the measures for the social and economic upliftment of Safai Karamcharis;
- (iv) the provisions of any law in its application to Safai Karamcharis; and take up such matters with concerned authorities or with the Central or State Governments;
- (d) To study and monitor the working conditions, including those relating to health, safety and wages, of Safai Karamcharis working under various kinds of employers including Government, Municipalities and Panchayats, and to make recommendations in this regard;
- (e) Make reports to the Central and State Governments on any matter concerning Safai Karamcharis, taking into account any difficulties or disabilities being encountered by Safai Karamcharis; and
- (f) Any other matter which may be referred to it by the Central Government.

2. The composition of the Commission, its powers, procedural matters, and preparation of its Annual Report will continue to be governed by para 3 and 5-7 of the above mentioned Resolution dated 9-9-2004.

P. P. MITRA, Jt. Secy.